दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 13.12.2023
उदघोषित: 08.01.2024

<u>आप.वि.वा.9128/2023 और आप.वि.आ. 34100/2023</u>

मंजिंदर सिंह सिरसा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आर. के. हांडू, श्री योगिंदर हांडू, श्री आदित्य चौधरी, श्री सोलंकी और सुश्री मेधा गौर, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वाराः श्री मनोज पंत, राज्य के लिए अति.लो.अभि.।
श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री नागिंदर बेनीपाल, श्री सुमित मिश्रा, सुश्री भारती नायर बेनीपाल, श्री नवीन चौधरी, श्री मारिथी कंबिरी और श्री अंकित सिवाच, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>न्याय की अनुक्रमणिका</u>

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि.....2

इस न्यायालय के समक्ष संबोधित तर्क..... 4

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे.....7

विश्लेषण और और निष्कर्ष.....7

i. आक्षेपित आदेश..... 8

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में जारी निर्देशों की जांच करना..... 9

iii. निष्कर्ष 15

<u>न्या. स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. याचिकाकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी-04, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा शिकायत मामला सं. 09/2023 शीर्षक *'मंजीत सिंह जी.के. बनाम मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य'* में दिनांक 06.12.2023 को पारित आदेश को रद्द करने और अपास्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण शिकायत को स्थानांतरित करने या वापस

करने की मांग करने वाले आवेदन को विद्वान ए.सी.एम.एम. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. वर्तमान याचिका दायर करने के लिए पृष्ठभूमि के तथ्य यह हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव सुधार लाने के उद्देश्य से, ***अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य*** रि.या.(सि.) 699/2016 में विभिन्न निर्देश पारित किए थे। ये निर्देश 01.11.2017 से शुरू होकर आदेशों की एक श्रृंखला में हैं, जिसके तहत दिल्ली राज्य सहित विभिन्न राज्यों में विशेष अदालत की स्थापना की गई, ताकि उन आपराधिक मामलों जिसमें सांसद/विधायक शामिल हैं का निपटान करने के लिए विचारण तेजी से किया जा सके। इसके बाद, 23.02.2018 की अधिसूचना के द्वारा दिल्ली में विशेष अदालत का गठन किया गया।

3. वर्तमान याचिका के द्वारा, यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त मामले में, दिनांक 09.11.2023 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्देश पारित किए गए थे, जिसके तहत विशेष अदालत को सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों के विचारण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, और 14.04.2017 को विधायक बने थे, हालाँकि, उन्होंने

11.02.2020 को विधायक नहीं रहे। यह कहा गया है कि इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा को भंग करने वाली दिनांक 11.02.2020 की अधिसूचना की प्रति का उल्लेख किया जा सकता है। यह कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता उक्त तारीख को विधायक नहीं रह गया है, और उसके खिलाफ उस अवधि में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जब याचिकाकर्ता विधायक नहीं रह गया था, क्योंकि आरोप 16.02.2020 के बाद की अवधि से संबंधित हैं, इसलिए उसके खिलाफ लंबित मामले की सुनवाई सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटान करने वाली विशेष अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है।

5. यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता है, ने साक्ष्य पेश किया था और कुछ गवाहों से पूछताछ भी की थी, जिसके आधार पर विद्वान ए.सी.एम.एम. ने वर्तमान याचिकाकर्ता को दिनांक 30.06.2023 को समन आदेश पारित किया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति की मांग करते हुए समन आदेश पारित करने के अनुसरण में, याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था, क्योंकि वह भारत में नहीं था, और कार्यवाही 17.07.2023 से 20.07.2023 तक स्थगित कर दी गई थी। इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शिकायत मामले को रद्द करने और ए.सी.एम.एम. द्वारा पारित समन आदेश को रद्द करने के

लिए याचिका दायर की थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 26.07.2023 को विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली थी। हालांकि, विद्वान सत्र न्यायालय, जिसके समक्ष समन आदेश को चुनौती दी गई थी, ने भी समन आदेश को अपास्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया था।

6. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण शिकायत की वापसी/स्थानांतरण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। दिनांक 06.12.2023 के आदेश के द्वारा उक्त आवेदन को विद्वान ए.सी.एम.एम. द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई।

<u>इस न्यायालय के समक्ष संबोधित तर्क</u>

7. **याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने**, दिनांक 06.12.2023 के आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विद्वान ए.सी.एम.एम. ने याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों को मूल्यांकन किए बिना नोटिस तैयार किय था। यह तर्क दिया जाता है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना के पीछे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का आशय देश में राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती लहर के कारण विधायकों के खिलाफ मामलों में तेजी लाना था, और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की सराहना की गई कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास जो शक्ति है, उसके कारण, विशेष न्यायालयों को मामले की शीघ्रता से सुनवाई करनी चाहिए। तथापि, यह कहा गया है कि एक बार जब

कोई व्यक्ति वर्तमान सांसद/विधायक नहीं रह जाता है और कथित अपराध उस अवधि से संबंधित होते हैं जब वह व्यक्ति सांसद/विधायक नहीं रह गया है, तो विशेष न्यायालय जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं कर सकता है, जो सांसद/विधायक नहीं रह गए हैं। यह जोरदार तर्क दिया गया कि एक बार विधायक, toतो हमेशा विधायक का मामला नहीं हो सकता है। यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवनकाल में एक बार सांसद/विधायक के पद पर रह चुका है, और बाद में जब वे उस पद पर नहीं रह गए, तो उसके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप का सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय द्वारा मामले का निपटान नहीं किया जाएगा।

8. यह भी तर्क दिया गया कि दांडिक विचारण दं.प्र.सं. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है, और विशेष न्यायालय के पास केवल वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की विचारण करने का अधिकार है, लेकिन उनके सांसद/विधायक नहीं रहने के बाद भविष्य के मामलों की नहीं। यह कहा गया है कि न तो विशेष न्यायालयों की स्थापना की अधिसूचना और न ही ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले

को वर्तमान मामले शामिल करते हैं, जहां यह उस अवधि से संबंधित है जब अभियुक्त सांसद/विधायक नहीं रह गया था।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि विशेष न्यायालयों के पास सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें मौजूदा सांसद/विधायक, या पूर्व सांसद/विधायक शामिल होंगे जिसके खिलाफ आपराधिक मामले पहले से ही लंबित थे या चुनाव के समय लंबित मामलों के रूप में घोषित किए गए थे। इस प्रकार, विशेष अदालत के पास याचिकाकर्ता पर विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो उस समय जब अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जब विधायक नहीं था और आज की तारीख में भी वह विधायक नहीं है।

10. यह तर्क दिया गया कि विद्वान ए.सी.एम.एम. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और उसके आशय को समझने में विफल रहा था, और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की गलत व्याख्या की थी। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान ए.सी.एम.एम. विधि के सिद्धांत को समझने में विफल रहा था, जिसे आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने ***कोलुसु पार्थ सारथी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** एम.ए.एन.यू./0528/2021 के मामले में अपने निर्णय में दिनांक 06.05.2021 को निर्धारित किया था। यह कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र की धारणा केवल इस आधार पर नहीं हो सकती है कि याचिकाकर्ता एक

बार विधायक/सांसद रहा था। इसलिए, यह कहा गया कि विद्वान ए.सी.एम.एम. द्वारा दिनांक 06.12.2023 को पारित आदेश को अपास्त किया जाए।

11. **प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता**, आक्षेपित आदेश को बनाए रखने की मांग करते हुए, तर्क दिए कि विद्वान ए.सी.एम.एम. द्वारा पारित आदेश एक तर्कसंगत आदेश है और इसमें कोई खामी नहीं है। यह भी कहा गया है कि विचाराधीन अधिसूचना, 23.02.2018 को ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जारी की गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्व विधायकों (सांसदों/विधायकों) के खिलाफ मामले के संबंध में भारत सरकार से विवरण मांगा था। यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों द्वारा, वर्तमान या पूर्व सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए निर्देश जारी किए गए थे और "पूर्व सांसद/विधायक" की श्रेणी में कोई अंतर नहीं है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता दिल्ली का पूर्व विधायक है, इसलिए विधायकों/सांसदों से संबंधित मामलों के विचारण के उद्देश्य से गठित विशेष अदालतों के पास वर्तमान मामले की विचारण करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, यह कहा गया है कि वर्तमान याचिका को गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

12. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संबोधित तर्कों को सुना है, और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

<u>इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे</u>

13. याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या सांसदों/विधायकों के मामलों का विचारण के लिए ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2018 को जारी अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष न्यायालयों को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है, जो कथित अपराध करने के समय कथित रूप से विधायक नहीं रह गए थे। मुद्दा यह भी है कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देश उन मामलों पर लागू होते हैं, जो किसी व्यक्ति के सांसद/विधायक नहीं रहने के बाद दर्ज किए गए हैं।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

14. इस न्यायालय ने विद्वान ए.सी.एम.एम. और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों सहित मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है, और ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निहित निर्देशों की भी जांच की है, जिसमें दिनांक 01.11.2017 के आदेश में विभिन्न निर्देश जारी किए

गए थे, और नवंबर, 2023 में पारित अंतिम आदेश सहित कई आदेश पारित किए गए थे।

15. अभिलेख पर की सामग्री पर विचार और विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान शिकायत में आरोप 16.02.2020 के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जब याचिकाकर्ता विधायक नहीं रह गया था। निस्सन्देह, याचिकाकर्ता को 14.04.2017 को विधायक के रूप में चुना गया था, और 11.02.2020 को वह विधायक नहीं रह गया था। यहाँ याचिकाकर्ता का मामला यह है कि इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या *35/डीएचसी/जीएजेड/जी-1/VI.ई.2(ए)/2018* दिनांक 23.02.2018 के अनुसरण में सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए गठित विशेष न्यायालय के पास वर्तमान शिकायत मामले की विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

i. आक्षेपित आदेश

16. प्रारम्भ में ही, यह न्यायालय दिनांक 06.12.2023 के आक्षेपित आदेश में विद्वान ए.सी.एम.एम.द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित समझता है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:

> "6. प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि आवेदन गुणागुण से रहित है।
>
> 7. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी सं.1 और 2 दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं।

8. यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि यह न्यायालय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 35/डीएचसी/जीएजेड/जी-1एनएलई.2(ए)/2018 दिनांक 23.02.2018 के अनुसरण में सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए गठित एक विशेष न्यायालय है।

9. उक्त अधिसूचना दिनांक 23.02.2018 को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य (पूर्वोक्त) शीर्षक मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.11.2017 और 14.12.2017 के आदेश द्वारा जारी की गई थी। दिनांक 1 के आदेश में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से उन मामलों के बारे में विवरण मांगा था जो 2014 और 2017 की अवधि के बीच वर्तमान या पूर्व विधानसभाओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और आगे, दिनांक 31.08.2020 के आदेश के द्वारा, मामले को फिर से उठाया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन की मांग की थी और उक्त आदेश में फिर से यह स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान मामले लंबित रहना निर्वाचित प्रतिनिधियों (वर्तमान या पूर्व) से संबंधित मामले के त्वरित निपटान में नहीं आएगी।

10. उपरोक्त दो आदेशों से यह स्पष्ट है कि सांसदों/विधायकों (वर्तमान या पूर्व) के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया था। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया था कि विशेष अदालतें केवल उन अपराधों पर विचारण करेंगी जहां अपराध किए जाने के समय अभियुक्त वर्तमान संसद सदस्य या विधायक हो।

11. इसी मामले में नवीनतम आदेश, अर्थात, रिट संख्या 699/2016 जिसका शीर्षक अश्विनी कुमार उपाध्याय (पूर्वोक्त) दिनांक 09.11.2023 है, में माननीय उच्चतम न्यायालय का यही आदेश प्रतीत होता है।

12. इस न्यायालय की राय में, सांसदों/विधायकों (वर्तमान या पूर्व) के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उक्त मामलों का शीघ्र निपटान हो ताकि दोषी विधायकों/सांसदों को राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधियों से मुक्त करने के उद्देश्य से आगे चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सके।

13. इसलिए, चाहे मौजूदा विधायक अपराध किया है या पूर्व विधायक द्वारा अपराध किया गया है, दोनों घटनाओं के मामले में सांसदों/विधायकों (वर्तमान या पूर्व) के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा निपटान किया जाना आवश्यक है।

14. इस मामले में, चूंकि आरोपी नंबर 1 और 2 पूर्व विधायक हैं, इसलिए इस अदालत का अधिकार क्षेत्र है..."

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में जारी निर्देशों की जांच करना

17. ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2017 को पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से विवरण मांगा था, जैसा कि ए.सी.एम.एम. ने ठीक ही कहा है, उन मामलों के बारे में जो 2014 और 2017 की अवधि के बीच वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2017 को पारित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है:

" विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री ए.एन.एस. नाडकर्णी ने शुरुआत में ही प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला कोई विरोधात्मक मुकदमा नहीं है और केंद्र सरकार राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े आपराधिक मामलों/अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और इसके शीघ्र निपटान के खिलाफ नहीं है।

उक्त बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए, हम केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित जानकारी न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं:

1. विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) से जुड़े 1581 मामलों में से कितने मामलों का निपटान [जैसा कि 2014 के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय घोषित किया गया था] इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 536/2011 में दिनांक 10 मार्च, 2014 को पारित आदेश द्वारा परिकल्पित एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर निपटान किया गया है।

2. इनमें से कितने मामलों का अंतिम निर्णय हो चुका है, सांसदों और विधायकों, जो भी हो के दोषमुक्ति/दोषसिद्धि के साथ समाप्त हो गए हैं।

3. 2014 और 2017 के बीच (आज की तारीख तक) क्या किसी वर्तमान या पूर्व विधायक (सांसद/विधायक) के खिलाफ कोई और आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और यदि हां, तो ऐसे मामले(लों) के निपटान के संबंध में विवरण सहित तत्संबंधी विवरण(णों) क्या है।

4. जहां तक विशेष न्यायालयों की स्थापना का संबंध है, विशेष न्यायालयों की स्थापना और अवसंरचना राज्यों के पास वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उपरोक्त मुद्दे पर उठाए गए विवाद में जाए बिना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित आपराधिक मामलों का निपटान करने के लिए विशेष रूप से न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय योजना होने से समस्या का समाधान किया जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पांच (05) वर्षों की अवधि के लिए स्थापित किया गया था और आगे बढ़ाया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

5. उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना अदालत के समक्ष अगली नियत तारीख को रखी जा सकती है जो विशेष अदालत की स्थापना के लिए निर्धारित की जा सकने वाली धनराशि उल्लिखित किया जा सकता है, जहां न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद और मानव-शक्ति और बुनियादी ढांचे की ऐसी अन्य

आवश्यकता (जो केंद्र सरकार से धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी) पर अदालत द्वारा, यदि आवश्यक हो, संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके कार्यवाही किया जाएगा।

श्री ए.एन.एस. नंदकर्णी, विद्वान ए.एस.जी. ने अदालत को आश्वासन दिया है कि उपरोक्त जानकारी को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत के समक्ष रखी जाएगी। तदनुसार, हम मामले को 13 दिसंबर, 2017 को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध करते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग को उन मामलों की प्रकृति को दर्शाने वाला शपथ पत्र अभिलेख पर लाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के तहत शक्ति का अतीत में प्रयोग किया गया है।

(जोर दिया गया)

18. इसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के प्रभावी निपटान करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए थे, और दिनांक 04.12.2018 के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार हैः

" हम **वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के प्रभावी निपटान करने के लिए अपने सुझाव तैयार करने** में विद्वान न्याय मित्र की सेवाओं की सराहना करते हैं, एक कार्य जो इस अदालत ने वर्तमान कार्यवाही में किया था।

इस मामले पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि विद्वान न्याय मित्र के सुझावों को कुछ संशोधनों के साथ और सीमित तरीके से आजमाया जाना चाहिए जो नीचे उल्लिखित किया गया है:

1. प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय और एक मजिस्ट्रेट न्यायालय को नामित करने के बजाय हम प्रत्येक उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि

वह **पूर्व और वर्तमान विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों** को इतने सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों को सौंपे/आवंटित करे जिन्हें प्रत्येक उच्च न्यायालय उचित, योग्य और समीचीन समझे। हमारे अनुसार, यह जिले में विशेष न्यायालय(यों) में **पूर्व और मौजूदा विधायकों से जुड़े सभी मामलों** को केंद्रित करने के बजाय एक अधिक प्रभावी कदम होगा।

2. उपरोक्त वर्णित विद्वान न्याय मित्र द्वारा इंगित प्रक्रिया संबंधी चरणों का पालन प्रत्येक नामित न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसे ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम आवंटित किया जाएगा, सिवाय इसके कि **वर्तमान सांसदों/विधायकों के साथ-साथ पूर्व सांसदों/विधायकों** के खिलाफ आजीवन कारावास/**मृत्युदंड** के दंडनीय अपराधों को पहली प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, जिसके बाद **मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों से जुड़े मामलों को बिना कोई भेदभाव किए ऊपर इंगित आनुक्रमिक क्रम से लिया जाएगा।**

3. इस स्तर पर, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्देश बिहार और केरल राज्यों के पूर्व और मौजूदा विधायकों से जुड़े मामलों पर लागू किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जहां स्थिति कुछ अलग है और दूरी और क्षेत्रों की कठिनाइयाँ विशेष अदालत (सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय दोनों) द्वारा मामलों की सुनवाई के तरीके में नहीं आती हैं, जारी रहेंगी..."

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.03.2020 के आदेश के द्वारा उच्च न्यायालयों को सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में एक निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः(i) किसी मामले में शामिल सांसद/विधायक, (ii) चाहे वह वर्तमान हो या पूर्व, (iii) प्राथमिकी की तारीख, (iv) कथित अपराध, (v) आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख, (vi) आरोप तय करने की तारीख, (vii)

वर्तमान स्थिति, (viii) उच्च न्यायालय द्वारा विचारण पर रोक, यदि कोई हो, (ix) विचारण के पूरा होने का अपेक्षित समय, (x) अदालत का नाम, और (xi) वह जिला जहाँ मामला दायर किया गया है।

20. इसके बाद, दिनांक 31.08.2020 को एक अन्य आदेश द्वारा, मामले को फिर से उठाया गया, जब याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में संशोधन की मांग की थी और उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* के मामले का लंबित रहना, निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी वर्तमान या पूर्व से संबंधित मामले के शीघ्र निपटान में आड़े नहीं आ सकता है।

> " हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वर्तमान मामले का लंबित रहना **निर्वाचित प्रतिनिधियों (मौजूदा या पूर्व) से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के रास्ते में नहीं आएगी।**
>
> सुनवाई की अगली तारीख को, हम विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को मामलों की निगरानी के साथ-साथ लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान करने के लिए कदम उठाने के बारे में कुछ निर्देश देने पर विचार करेंगे।"
>
> (जोर दिया गया)

21. इस न्यायालय की राय में, जब उपरोक्त आदेश दिनांक 01.11.2017, 04.12.2018, 05.03.2020 और 31.08.2020 को एक साथ जारी किया गया था, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष अदालत का गठन विधायकों यानी सांसदों या विधायकों चाहे वे मौजूदा हों या पूर्व, के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए किया गया था।

22. इसलिए, चारों आदेशों के उपर्युक्त पठन से अनिवार्यतः जो आवश्यक अनुमान किया जा सकता है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेष अदालत का गठन मौजूदा या पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ कथित अपराधों के विचारण के लिए किया गया था, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि विशेष अदालतें केवल उन अपराधों की सुनवाई करेंगी जहां आरोपी अपराध के समय मौजूदा सांसद/विधायक थे।

23. उपरोक्त कानूनी परिदृश्य में, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से परे नहीं जा सकता है, और जब ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्देश पारित करते समय प्रयुक्त की गई शब्दावली को अवलोकित किया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्पष्ट रूप से "पूर्व सांसदों/विधायकों" के बीच कोई विशेष भेदभाव किए बिना स्पष्ट रूप से "पूर्व सांसदों/विधायकों" को संदर्भित किया है। **नतीजतन, इस न्यायालय के पास निर्णय की व्याख्या इस तरीके से करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों से मार्ग से अलग हो जाए। दूसरे शब्दों में, यह न्यायालय पंक्तियों के बीच कुछ भी नहीं पढ़ सकता है, जो न तो आशय है और न ही सामग्री, निष्कर्ष या यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इतरोक्ति है।**

24. इस संबंध में ***अश्विनी कुमार उपाध्याय*** *(पूर्वोक्त)* में 09.11.2023 को पारित दुसरे आदेश का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा, जिसमें निम्नानुसार टिप्पणियाँ की गई हैः

> "14. इन मामलों का सीधा असर हमारे राजनीतिक लोकतंत्र पर पड़ता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और जल्द से जल्द निर्णय किया जाए। संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी, संवादात्मक, और कुशल कामकाज के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो या विधायक पर निर्वाचन क्षेत्र का विश्वास आवश्यक है। हालाँकि, इस तरह के विश्वास की उम्मीद करना मुश्किल है जब आंकड़े, जैसा कि ऊपर उल्लिखित तालिका में इंगित किया गया है, हमारी राजनीति में बहुत अधिक हैं।
>
> 15. वास्तव में, विषयगत मामलों को तेजी से उठाने और निपटान करने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन में शामिल राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो या विधायक, भी इन मामलों के त्वरित निपटान करने की मांग करेंगे। लेकिन समस्या कहीं और है। यह प्रणालीगत, शायद संस्थागत प्रतीत होता है, और प्रतिकूल मुकदमेबाजी के तरीके सहित कई कारकों को अपने दायरे में लेता है जिसे हमने अपनाया है। फिर भी, हम जिस कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके हर चरण में सुधार की गुंजाइश है। यह इस संदर्भ में है कि हमने पिछले सात वर्षों से इस मामले को ईमानदारी से संचालित और निगरानी की है।"

25. उपरोक्त आदेश को पढ़ने से यह भी पता चलेगा कि मौजूदा या पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ दायर मामलों का निपटान करने के लिए विशेष

अदालत का गठन करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनके खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई तेजी से की जाए।

iii. निष्कर्ष

26. निस्सन्देह इसमें याचिकाकर्ता एक पूर्व विधायक है और यह तर्क कि कथित अपराध के समय वह विधायक नहीं रह गया था, सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटान करने के लिए गठित विशेष अदालत द्वारा उसके मामले पर विचारण पर रोक नहीं हो सकती है। इस न्यायालय की यह भी राय है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय को यह समझाने में विफल रहे हैं कि कैसे उनके मामले की त्वरित विचारण के कारण याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

27. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान ए.सी.एम. एम. के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समग्र पठान से पता चलता है कि विशेष अदालत मौजूदा या पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित अपराधों पर विचारण कर सकती हैं, और ऐसे व्यक्ति पर विचारण पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है जो सांसद/विधायक नहीं रह गया था, जब उसने कथित रूप से अपराध किया था।

28. इसलिए, यह न्यायालय विद्वान ए.सी.एम.एम. के निर्णय से सहमत है, जिसके तहत यह कहा गया था कि चाहे मौजूदा विधायक कोई अपराध किया है

या कोई अपराध कथित रूप से किसी पूर्व विधायक द्वारा किया गया है, उस मामले का विचारण विशेष अदालत द्वारा की जा सकती है, जो सांसदों/विधायकों चाहे वह मौजूदा हो या पूर्व, के खिलाफ मामलों का निपटान करने के लिए स्थापित की गई है।

29. उपरोक्त परिस्थितियों में और ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस न्यायालय को विद्वान ए.सी.एम.एम. द्वारा दिनांक 06.12.2023 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है।

30. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

31. फैसला तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

8 जनवरी, 2024
आंचल

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*